# सी. बी. डी. सी / ई – रुपी - को कहें ' ना '

## (C.B.D.C – सेंट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी)

हमारी सरकार का कहना है कि मुद्रा छपाई में बहुत धन का उपयोग होता है जो कि अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है जैसे कि गरीबों की देखभाल करना आदि। पहले भी वह संकेत दे रहे थे कि हमें एक कैशलेस समाज की ओर जाना चाहिए और इसलिए वह कहते हैं कि हमें CBDC या सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा के लिए जाने की आवश्यकता है। अगर वास्तव में हम एक डिजिटल सिस्टम की बात करें तो पहले से ही यू.पी.आई, नेट बैंकिंग, आदि का उपयोग कर रहे हैं ; तो फिर से एक नया सिस्टम क्यों ? और कितना अलग है यह C.B.D.C ?

मौजूदा डिजिटल भुगतान विधियों के मामले में, दो बैंकों के बीच का कुल लेनदेन आर.बी.आई (R.B.I) को सूचित किया जाता है। प्रत्येक व्यक्तिगत लेनदेन का विवरण केंद्रीय बैंक (Central Bank) को नहीं जाता है, अभी यहाँ भारत में, जो आर.बी.आई है। उदाहरण के लिए – आपने आज एक वस्तु खरीदी, आपकी खरीदी का विवरण आर.बी.आई को नहीं पता है। परंतु C.B.D.C या E-रुपी के साथ, प्रत्येक लेनदेन विवरण RBI को ज्ञात होगा जोकि खुद इसे नियंत्रित करेगा। इस प्रकार हर लेनदेन जो आप करेंगे, वह आर.बी.आई और केंद्र सरकार को ज्ञात होगा।

**- इसलिए आपकी गोपनीयता दाव पर है।**

अब जैसे कि आप एक विशेष संगठन को दान दे रहे हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध कर रहा है, फिर उस लेनदेन को आसानी से प्रतिबंधित (Transaction Block) किया जा सकता है। या अगर आपको सरकार की नीतियों का विरोध करते देखा गया तो फिर से आपका पैसा अनुपयोगी कर दिया जाएगा। - एक स्वतंत्र देश में वह ऐसा कैसे कर सकते हैं ?

क्योंकि यह मुद्रा एक 'प्रोग्रामेबल' मुद्रा होगी। इसलिए इसे आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं, कि कहाँ इसका उपयोग किया जाए और किन उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाए।
ए-आई और प्रासंगिक सॉफ्टवेयर की मदद से यह सम्भव है। जबकि नियमित डिजिटल भुगतान में आप तय करते हैं कि किसे-कब भुगतान करना है। जब की सी.बी.डी.सी के मामले में सरकार तय करेगी कि कहाँ आप अपना पैसा खर्च करें और किसलिए।

**- आप अपनी मेहनत से कमाए पैसों को खर्चने का हक खो देंगे।**

अब जब सरकार आपके पैसों को नियंत्रित करेगी, तो आपको नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाएगा। इस प्रकार वह तय कर सकते हैं कि आपको एक निश्चित नीति के खिलाफ विरोध करने का अधिकार होगा या नहीं। हमारे मूल मौलिक अधिकार जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, एक नागरिक के रूप में जो हमारे संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं, इस लोकतंत्र में एक आम नागरिक की बातों को बहुत आसानी से आवाज़ दी जा सकती है। लेकिन केवल हमारी मुद्रा को बंद कर, इसे निरर्थक बनाया जा सकता है। हम पहले से ही यह देखते हैं कि किसी भी कुनीति का विरोध करना कितना मुश्किल हो गया है। सरकार इस सी.बी.डी.सी के साथ नागरिकों पर कुल नियंत्रण हासिल कर लेगी।

**- हमारे बुनियादी अधिकार आसानी से छीने जा सकते हैं।**

अब सी.बी.डी.सी के साथ-साथ आधार-पैन और आपके बैंक खाते के जोड़ से सरकार आपके धन पर पूर्ण नियंत्रण कर लेगी। इसके साथ ही - आपका चेहरा पहचानने का सॉफ्टवेयर, आपकी हर हरकत तथा स्थान की निजि जानकारी पर नज़र रखना बहुत आसान हो जाएगा। फिर नागरिकों को सत्ता में रहने वालों द्वारा देखे जाने के निरंतर भय में जीना पड़ेगा, जैसा कि चीन में आज होता है। फिर यह देश लोकतंत्र से एक तानाशाही व्यवस्था बन जाएगा (जो केवल नाम का लोकतंत्र होगा)।

**- अब सच में लोकतंत्र खतरे में है।**

इतना ही नहीं, सी.बी.डी.सी एक 'समय-समाप्ति' के साथ प्रोग्राम करने योग्य धन-राशी है। मान लीजिए कि आपने बैंक में एक निश्चित राशि बचाई है और अभी आप इसे खर्च नहीं करना चाहते हैं ताकि आवश्यक्ता अनुसार भविष्य मे इसका उपयोग करें ; लेकिन CBDC के साथ, जिसमें 'समय-समाप्ति' तिथि होगी, आपके खाते में पैसा होकर भी बेकार हो जाएगा, जब तक कि आप उस समय सीमा के भीतर इसे खर्च नहीं कर देते; जैसा कि आर.बी.आई तय करेगी।

**आप अपनी सभी बचत खो देंगे और ना ही भविष्य के लिए बचा पाएंगे।**

अब आप **प्रश्न** करेंगे कि – **'हमारे द्वारा ही चुने हुए नेता जन ऐसा क्यों कर रहे हैं ?'**

**उत्तर - अगर हम पिछले 2-3 दशकों से देखें तो विशेष रूप से हमारी सरकारों ने नीतियाँ विदेशियों के सुझावों पर बनाई हैं – जैसे कि विश्व बैंक, आई.एम.एफ, डब्ल्यू.टी.ओ, डब्ल्यू.ई.एफ आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिन्होंने हमें उन नीतियों को लागू करने के लिए ऋण दिया है। जिससे कि वास्तव में हमें आजीविका का नुकसान, कृषि संकट, स्वास्थ्य हानि तथा नुक्सानदेह टीके, किसानों की आत्महत्या, छोटे व्यवसायों का बंद होना, आदि कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। आज ऐसे संगठन कुछ निगमों , क्लाउस श्वाब और बिल गेट्स जैसे अरबपतियों द्वारा नियंत्रित होकर रह गए हैं। और इस प्रकार, पूरी दुनिया में इन नीतियों को जबरन लागू करवाया जा रहा है और यह सब एक नई 'विश्व सरकार' या 'New World Order' की ओर अग्रसर है।**

## हमारी संप्रभुता और हमारी स्वतंत्रता दाव पर है!

* * * * *

## आवाज़ उठाओ...कहीं देर ना हो जाए ...

**CBDC से कैसे लड़ें?**

१. **दैनिक जरूरतों के लिए नकदी का उपयोग करें।**
   **सुविधा से ज़्यादा स्वतंत्रता को प्राथमिकता दें।**
२. **नकद भुगतान के खिलाफ भेदभाव करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें।**
३. **प्रधानमंत्री को पत्र लिखें (पोस्टकार्ड, ई-मेल, ट्विटर, फेसबुक आदि से) नागरिक के रूप में इस गणतंत्र के आप CBDC को अस्वीकार करते हैं।**
४. **इस संदेश को दूर-दूर तक फैलाएं और भारत को लुटेरों के चंगुल से बचाएँ !**

## सी. बी. डी. सी - नहीं चलेगा ... नहीं चलेगा ...
## जागो भारत ... जागो...

**अवेकन इंडिया मूव्मेंट द्वारा जनहित में जारी...**

https://awakenindiamovement.com/